सीमित प्रसार के लिये

कारीगर नज़रिया

● यह कारीगर समाज का ज्ञान आंदोलन है। ●

● कारीगर समाज अपने नज़रिये पर फक्र करें। उसका नज़रिया, उसकी विद्या उसका हुनर पढ़े-लिखे लोगों के मुकाबले कम दर्जे का नहीं है। ●

● कारीगर नज़रिये पर गढ़ी गई दुनिया आज की दुनिया से एक बेहतर, खुशहाल और बराबरी की दुनिया बनेगी। ●

अंक 4 | मार्च 2014 | सहयोग राशि : 2 रुपये

संपादकीय

देश के कारीगरों को कारीगर नज़रिया का अवाहन

कारीगर खुशहाल हों इसके लिए

कारीगर–समाज देश का एजेण्डा बनायें

जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने और समाज को उपलब्ध कराने का काम देश का कारीगर समाज करता है। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, कपास, कपड़ा, काँच आदि अनेक पदार्थों को उपयोग लायक बनाना, उनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना, स्वास्थ्य व खाद्य की वस्तुओं का निर्माण कर लोगों तक पहुँचाना आदि बहुत सारे काम कारीगर समाज के बूते ही हो रहे हैं। हमारे देश में किसान समाज के बाद कारीगर समाज ही सबसे बड़ा समाज है। दोनों मिलकर देश का 80-85 फीसदी हैं। बुनकर, मल्लाह, रजक, नाई, प्रजापति, विश्वकर्मा, वनवासी समूहों की अनेक जातियाँ कारीगर जातियाँ हैं और इनके अलावा बिजली, भवन, पानी, मोटर, बाइक, टीवी, कम्प्यूटर व सभी मशीनों के तरह-तरह के मिस्त्री ये सब कारीगर हैं।

ये सब कारीगर और किसान समाज अपने ज्ञान के बल पर अपना जीवन चलाते हैं, स्कूल या कॉलेज की विद्या के जरिये नहीं। **इनके ज्ञान को लोकविद्या कहते हैं।** इस लोकविद्या-समाज के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती। राजनैतिक पार्टियों के एजेण्डे से ये गायब हैं। किसानों और कारीगरों की यह जरूरत है और देश की खुशहाली की यह माँग है कि ये लोग आगे बढ़कर यह देश कैसा होना चाहिए, देश की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, इन विषयों पर अपनी राय दें। **लोकविद्या का जानकार समाज आगे बढ़कर देश का एजेण्डा तय करे।**

कारीगर और किसान समाजों को खुलकर यह कहना होगा कि इस देश के नेता, पूँजीपति और प्रोफेसर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की गरीब जनता को और गरीब बना रहे हैं। ये गरीब लोग किसान, कारीगर, आदिवासी और छोटा-छोटा दुकानदार हैं। ये सब लोकविद्या के स्वामी हैं और उसी के बल पर अपना परिवार और समाज चलाते हैं। इन्हें एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर यह दावा पेश करना है कि देश का एजेण्डा वे बनायेंगे।

देश का एजेण्डा बनाने की यह प्रक्रिया नीचे दिये पाँच बिन्दुओं से शुरू की जा रही है।

1. **लोकविद्या के बल पर जीना यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।** इसलिए जमीन से विस्थापन और रोजगारों का छीना जाना पूरी तरह बन्द हो और कारीगर, किसान व आदिवासियों के उत्पादन को जायज मूल्य मिले।
2. **ज्ञान के क्षेत्र में ऊँच-नीच बिलकुल नाजायज है।** लोकविद्या को विश्वविद्यालय के ज्ञान के बराबर का दर्जा होना चाहिए। इसलिए लोकविद्या के आधार पर काम करने वालों की आय नियमित और पक्की की जाये तथा यह आय सरकारी कर्मचारी के बराबर हो।
3. **राष्ट्रीय संसाधनों का बराबर का बँटवारा हो।** बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, वित्त इन सबकी व्यवस्थाएँ सबके लिए समान हों।
4. **स्थानीय व्यवस्थाओं पर स्थानीय समाजों का नियंत्रण हो।** इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय बाजार और प्रशासन पर स्थानीय समाजों का नियंत्रण हो तथा स्थानीय उद्योगों और स्थानीय बाजार में बड़ी पूँजी की घुसपैठ पर रोक हो।
5. **हर गाँव और हर बस्ती में मीडिया स्कूल हो।** इन स्कूलों में युवाओं को यह सिखाया जायेगा कि उनकी अपनी बात क्या है, उसे कैसे कहना है, किससे कहना है, कहाँ दावा पेश करना है, आपस में वार्ता की विधायें क्या होनी हैं, और इन सब बातों का कैसा ताना-बाना हो कि बदलती दुनिया में बराबरी और खुशहाली की जिन्दगी के लिए परिस्थितियाँ बनायी जा सकें।

अधिक से अधिक संख्या में कारीगर और किसान एक साथ आयें और देश की खुशहाली के इस नये एजेण्डा का पैगाम घर-घर तक पहुँचायें।

●

खुशहाली का रास्ता

–एहसान अली

आज 65 वर्ष हो गये आजादी के और कारीगर, कारीगर न रहकर मजदूर बन गया। शोषण में रियायत और रियायत में शोषण देखने का एक तरीका तरह-तरह के कार्ड-रेशम कार्ड, आवास, मिड-डे-मील, स्वास्थ्य कार्ड, सफेद कार्ड के रूप में देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी नीति हमें इस रूप में गरीब मजदूर बनाये रखने की है। रियायत के नाम पर हमें लूटने की है।

वास्तव में यदि सरकार चाहती है कि कारीगर खुशहाल रहें तो सबसे पहला काम करें कि हमें मजदूर न मानें, न बनाये। हमें ज्ञानी का रुतबा दे और हमारे बीच में आकर बैठक करके हमारे हालात को हमारी नजर से समझे। ठीक वैसे ही जैसे बड़े पूँजीपतियों-उद्योगपतियों के बीच बैठकर उनके अनुसार सोचने-विचारने की नीतियाँ बनाने का कार्य सरकारें करती हैं।

कारीगर के काम पर गौर करें, वह रात-दिन बिजली की आवाजाही के अनुसार 12-14 घंटे खटता है, जबकि सरकारी कार्यवधि 8 घंटे की ही होती है। हमारे लिए हमारे ज्ञान के बल पर **'पक्का काम, पक्की आय'** जो सरकारी कर्मचारी के समान हो, की व्यवस्था होने पर ही सामान्य जीवन जीने का हमारा ख्वाब पूरा हो सकेगा।

अपील व सम्पर्क

'कारीगर नजरिया' कारीगर समाज का अखबार है। इसमें कारीगर अपनी समस्याओं, माँगों, क्षमताओं और समाज के बारे में अपने नजरिये को सामने लायें।

सम्पर्क पता :

सी. 27/249-10, विवेकानंद नगर कालोनी, जगतगंज, वाराणसी-221002

सम्पर्क फोन :

दिलीप कुमार 'दिली', मो. 9452824380

एहसान अली, मो. 9336016119

प्रेमलता सिंह, मो. 9369124998

लोकविद्या जन आंदोलन का आवाहन

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई तहसील में 1998 में किसानों की एक सभा पर पुलिस प्रशासन ने ऐसी गोली चलायी थी कि 24 किसान मारे गये थे। तब से वहाँ की किसान संघर्ष समिति हर साल उस दिन, 12 जनवरी को देशभर के किसान संगठनों को बुलाकर 'शहीद किसान स्मृति' का आयोजन करती है। इस वर्ष विद्या आश्रम, वाराणसी ने देशभर के लोकविद्या जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसने लोकविद्या-समाज को आवाहन दिया कि आगे बढ़कर देश का एजेण्डा बनायें। कहा कि किसान, कारीगर, आदिवासी और छोटा दुकानदार एक पाँच बिन्दुओं के कार्यक्रम से देश का एजेण्डा बनाना शुरू करें। ये पाँच बिन्दु वही हैं जो बगल में छपे सम्पादकीय में दिये गये हैं।

●

आखिर कितना भेदभाव?

सरकारी कर्मचारी का वेतन सरकार द्वारा बनाये वेतन आयोग तय करते हैं। न्यूनतम वेतन तय करने का आधार होता है—'जीने की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक वेतन'। अलग-अलग समय पर तय किये गये ये न्यूनतम वेतन नीचे दिये जा रहे हैं :

महँगाई भत्ता इन वेतनों में हर छः माह में जुड़ता जाता है और दस साल में वेतन लगभग दुगना हो ही जाता है। यानि अब जो वेतन आयोग बनेगा वह लगभग 20,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन तय करेगा और दुनिया भर की सुविधाएं अलग से। इसके सामने कारीगरों की दुनिया कैसी बदहाल नजर आती है।

वर्ष	वेतन आयोग द्वारा तय न्यूनतम वेतन
1946	55 रुपये प्रति माह
1959	80 रुपये प्रति माह
1973	196 रुपये प्रति माह
1986	750 रुपये प्रति माह
1996	2550 रुपये प्रति माह
2006	7000 रुपये प्रति माह

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अपने ज्ञान के बल पर काम करने वाला हर कारीगर इस न्यूनतम आय से अधिक का हकदार बनता है। फिर ऐसा अत्याचार और भेदभाव क्यों?

क्या कोई पार्टी या सरकार इस भेदभाव को खतम करने की बात भी नहीं करना चाहती?

●

निमंत्रण

किसान–कारीगर देश का एजेण्डा बनायें

विद्या आश्रम, सारनाथ में 10-11 फरवरी 2014 को लोकविद्या जन आन्दोलन कार्यकर्त्ता, किसान व कारीगर संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि किसान और कारीगर समाज एक साथ मिलकर देश की नीतियाँ बनाने में आगे आयें तभी इन समाजों को बदहाली से निजात मिलेगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के 8-9 जिलों के किसान यूनियन के नेता, वाराणसी से कारीगर संगठन, बिहार व मध्यप्रदेश के लोकविद्या जन आन्दोलन के कार्यकर्त्ता तथा किसान संघर्ष समिति के कुल लगभग 100 लोग उपस्थित थे। बैठक में निम्नलिखित जिलों में किसान-कारीगर पंचायतें आयोजित कर एजेन्डा बनाने का कार्य शुरु करने का निर्णय लिया गया। **सभी पंचायतें दिन में 11 बजे से शुरु होंगी।**

1. **2 मार्च 2014,** स्थान : शहर वाराणसी, एस.एस. कान्वेन्ट स्कूल, मुहम्मद शहीद मस्जिद के सामने, पीली कोठी। **सम्पर्क :** एहसान अली, कारीगर नजरिया (मो. 8303244310)।
2. **3 मार्च 2014,** स्थान : जिला गाजीपुर, गाँव रानीपुर, ब्लाक मदरह। **सम्पर्क :** दिनेश पाण्डेय, जिलाध्यक्ष भाकियू, गाजीपुर (मो. 9598494310)।
3. **4 मार्च 2014,** स्थान : जिला वाराणसी, जगदेव प्रसाद स्मारक, गाँव सलारपुर, ब्लाक चिरईगाँव। **सम्पर्क :** लक्ष्मण प्रसाद, जिलाध्यक्ष भाकियू, वाराणसी (मो. 9026219913)।
4. **5 मार्च 2014,** स्थान : जिला चन्दौली, गाँव महरखां, ब्लाक चहनियां। **सम्पर्क :** जितेन्द्र तिवारी, जिलाध्यक्ष भाकियू चन्दौली (मो. 9889994268)।
5. **6 मार्च 2014,** स्थान : जिला जौनपुर, मड़ियाहू। **सम्पर्क :** राजनाथ यादव, जिलाध्यक्ष भाकियू जौनपुर (9161551285)।

अधिक से अधिक संख्या में किसान और कारीगर इन पंचायतों में शामिल होकर अपनी और देश की खुशहाली के रास्ते बनाने में भाग लें और पंचायत का पैगाम घर-घर तक पहुँचायें।

'कारीगर नजरिया' कार्यालय पर

कारीगर समाज की बैठकें

कारीगर का जीवन खुशहाल कैसे हो, इस मुद्दे पर 'कारीगर नजरिया' के कार्यालय पर प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को बैठक होती है। अब तक ऐसी दो बैठकें हो चुकी हैं और इस माह 23 फरवरी को होगी। इन बैठकों में वाराणसी शहर के और आसपास के क्षेत्रों से कारीगर आते हैं। अभी तक बुनकर समाज के लोग अधिक संख्या में आते रहे हैं। बैठक के अंत में सर्व सहमति से एक ज्ञापन तैयार किया जाता है और इसे जन प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को इस इरादे से दिया जाता है कि इन ज्ञापनों के आधार पर करीगरों की ओर से देश के लिए एक एजेण्डा बनाया जा सके। अब तक ये ज्ञापन जिलाधिकारी, हथकरघा निदेशक, विधायकों, सांसद व लोक संस्कृति राज्य मंत्री को दिया गया है। आगामी आम चुनाव में खड़े हो रहे सभी उम्मीदवारों को भी दिया गया है। इस ज्ञापन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया है।

1. **वस्तुओं का उत्पादन करने वाला व्यक्ति कारीगर कहलाता है, उसे मजदूर कहना उसका अपमान है। इसलिए बुनकर खुद को मजदूर कहना बन्द करें और दूसरों को भी यह समझायें।**
2. **हर कारीगर परिवार की नियमित और पक्की आमदनी हो। यह आमदनी सरकारी वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए तय तनख्वाहों से मेल खाने वाली हो। (आज की तारीख में कम-से-कम 1000/- प्रतिदिन)।**
3. **बिजली की आपूर्ति कम-से-कम 20 घंटे हो और दिन में कटौती न हो।**

बुनकर की नजर में समस्या और सुझाव

–फज्लुर्रहमान अंसारी उर्फ आलम

बनारस का सदियों पुराना बनारसी साड़ी उद्योग पिछले कुछ सालों से धागे की कीमत में अप्रत्याशित तौर पर रोज-ब-रोज बेतहाशा बढ़ोत्तरी की वजह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है। हर एक दिन के अंतर पर 40 से 50 रुपये प्रति किलो की दर से कीमतों में इजाफे की वजह से बुनकर अपने उत्पाद की कीमत ही मुकर्रर नहीं कर पाता। नतीजेस्वरूप अपने बनाये माल के लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

जिस प्रकार से पांच महीने के अन्दर धागे के दामों में 50 से 80% की बढ़ोत्तरी हुई है, उससे साफ जाहिर है कि यह जमाखोरी और मुनाफाखोरी है। इस बढ़ती मुनाफाखोरी को रोकने का कोई रास्ता दिखलायी नहीं देता है।

बुनकर समाज, सरकार द्वारा थोपी गयी बदहाल आर्थिक नीतियों के चलते ही बिजली बकाया जमा नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर बिजली बकाया वसूली की आड़ में विभाग के अधिकारियों द्वारा नाजायज रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। कनेक्शन काटने और जेल भेजने की धमकियां दी जाती हैं और हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली की जाती है।

देश का किसान अगर लोगों का पेट भरने का काम करता है तो बुनकर तन ढँकने के लिए कपड़ा देता है। आज दोनों की हालत बदतर है। बुनकर न ही अपने बच्चों को ठीक से तालीम दिला पाते हैं और न ही पेट भर भोजन। और जब भोजन पेट भरने के लिए नहीं मिलता तो स्वास्थ्य की बात क्या करें? यह कहने-सुनने की नहीं, देखने और चिन्ता करने का सवाल है।

यदि कुछ कार्यक्रम बुनकरों की राय से लिये जायें तो बुनकर की स्थिति सुधर सकती है। बुनकरों की आबादी के मुहल्लों में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाय जहां रंगाई, बुनाई, सफाई से लेकर हर किसम के धागों और डिजाइनों पर रिसर्च करके नये-नये प्रयोग किये जाये जिससे बुनकर आज के दौर में एक से एक बेहतर रंग और डिजाइन के माल बना सके। इस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए हमारे बुनकर समाज के अनुभवी लोगों को ही रखा जाय। सरकारी ट्रेनर की तरह उन्हें वेतन मिले।

चाइना निर्मित रेशम पर और कपड़ों पर 30% कस्टम ड्यूटी लागू किया जाय ताकि देशी रेशम, केला व वैंगलुरु रेशम अधिक खपे। बुनकरों के बिजली बकाये को माफ किया जाय। फिक्स रेट पर बिजली दी जाय, बुनकरों को मनरेगा की तर्ज पर काम दिया जाय। बुनकर अस्पतालों की सुविधा जन-मशविरे के आधार पर बढ़ायी जाय। बुनकरों के बच्चों की स्कूली तालीम के लिए विद्यालय खोले जाये और उसकी जिम्मेदारी उस बस्ती के अनुभवी-गुणी जनों को सौंपी जाय।

आन्ध्र प्रदेश में बुनकर रैली

आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा के कारीगर एक आंदोलन के दौर में हैं। 'चेतना जन समाख्या' नाम के बुनकर संगठन के नेता ओर 'लोकविद्या जन आंदोलन' के कार्यकर्ता माचरला मोहनराव के साथ 20 कार्यकर्ताओं ने 30 जनवरी 2014 को चिराला से शुरू करके एक पदयात्रा निकाली, जो 12 फरवरी को हैदराबाद पहुँची। चिराला हथकरघा बुनकरों का नगर है और हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की राजधानी। इस पदयात्रा ने रास्ते में हथकरघा बुनकरों के गाँवों चिलकलुरीपेट, पिडुगुरल्ला, नरसारावपेट, मिर्यलगोडा, नलगोंडा और पोचमपल्ली से होते हुए 460 किलोमीटर की दूरी तय की। हैदराबाद में 13 फरवरी को इन्दिरा पार्क के मैदान में आन्ध्र पेदश में, बुनकरों के बीच काम कर रहे और संगठनों के साथ मिलकर एक रैली का आयोजन किया गया और राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु हैं—

1. सभी राजनैतिक दलों से यह मांग की जाती है कि हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को उनके घोषणापत्र में शामिल किया जाय। कपास उत्पादक, बुनकर रंगरेज, कपड़ा बेचने वाले इनकी तादाद करोड़ों में है और ये भूखमरी की हालत में ढकेल दिये गये हैं।
2. भारत सरकार ने ग्यारह तरह के आरक्षण हथकरघा क्षेत्र के लिए लागू किये हैं, जिनका प्रशासन द्वारा अक्सर उल्लंघन किया जाता है। ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और इन नीतियों को लागू करने का अधिकार ग्रामपंचायतों को मिलना चाहिए।
3. हथकरघा बहुल गाँवों में इनके कपड़े के लिए खरीद केन्द्र खोले जाने चाहिए तथा इसके लिए रुपये 300 करोड़ आवंटित किया जाय।
4. राज्य के बजट में हथकरघा बुनकरों व अन्य दस्तकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए रुपये 500 करोड़ आवंटित किये जायें।

–टी. नारायण राव और के. जे. रामाराव,
लोकविद्या जन आंदोलन

बुनकर महिलाओं की जुबानी

–प्रेमलता सिंह

अजीजुन्निशा, पति अब्दुल रऊफ, उम्र 65 वर्ष वाराणसी के मुर्गीया टोला, पीली कोठी की क्षेत्र से हैं वे कहती हैं कि पुरुष हथकरघा के कारीगर हैं, पर औरतें घर में नाका टिक्की का काम करती हैं।

अजीजुन्निशा जी को 6 बेटे हैं। सभी बाल-बच्चेदार हैं। मजदूरी पर कार्य करते हैं। सबके अपने करघे हैं। हथकरघा की कारीगरी की मजदूरी से दाल-रोटी नहीं चलती, बिजली रहती नहीं, मंदी की मार अलग से। मंदी होती है तब मालिक के यहाँ से काम नहीं मिलता। सभी औरतें बच्चियाँ मिलकर नाका टिक्की का काम करती हैं। बिरल बूटी (लगभग एक फीट के अंतर पर) की एक साड़ी टांकने में दो लड़कियों को चार से पांच घंटे लगते हैं और मजदूरी सिर्फ 30/- मिलती है। अकेले बनाना हो तो आठ से दस घंटे लगेंगे। अब तो हथकरघा की डिजाइन पावरलूम पर बनने लगी हैं। सरकार इसे रोके। हथकरघा वैसे ही गिनती के रह गये हैं, अब जो बचे हैं वो भी बंद ही हो जायेंगे। हमारे जैसा गरीब बुनकर का परिवार पावरलूम नहीं लगा सकता। हमारे मुहल्ले मुर्गिया टोला, कटेहर, कोदोपुर की हालत बारिश में इतनी बदतर हो जाती है कि करघे की खड्डी पानी में डूब जाती है। काम तो बंद हो ही जाता है लेकिन हम घर से बाहर भी नहीं निकल पातीं। क्योंकि रास्ते-गली में इस कदर पानी लगता है कि कई दिन तक निकल ही नहीं पाते। इस साल ऐसी मंदी रही कि हमलोगों को पांच महीना कोई काम ही नहीं मिला। **'पक्का काम और पक्की आय'** का अभियान 'कारीगर नजरिया' ने छेड़ा है यह जानकर अजीजुन्निशा बेहद उत्साहित हैं और उसमें उनके बेटे जरूर शामिल होंगे यह कहती हैं।

●

तारकशी के कारीगरों को आवाहन

बाकराबाद में बिटाई के कारीगरों से मुलाकात के दौरान 62 वर्ष के बुजुर्ग हरिदास जी ने कहा कि बिटाई (तारकशी) का काम तो बहुत पहले ही टूट गया। मशीन कूड़े के भाव बिक गये। इसी तरह मनबोध ने कहा कि पहले खुद की मशीन पर वे खुद बिटाई का काम करते रहे हैं। अब दूसरों से काम लाकर अंटा भरते हैं। 12 घंटे काम से मुश्किल से रुपये 60-70 प्रति दिन कमा पाते हैं। बिजली मिले तो भी रुपये 100/- से ज्यादा नहीं कमा पायेंगे।

रामनरेश मौर्य कहते हैं कि हमारे काम की कोई गारंटी नहीं है। सरकार से हम काम की गारंटी चाहते हैं और कम-से-कम 350-400 रुपये प्रतिदिन की आय की मांग करते हैं।

अनिल कुमार जरी के कारीगर हैं। वे कहते हैं कि आटोमेटिक मशीन आने के बाद से बुनकर का काम बदल गया। हमारी जरी की मांग घट गयी। एक दिन में बस 100/- रुपये कमा पाते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि प्लास्टिक जरी का काम खत्म होगा और हमारी हालत सुधरेगी। हम जो काम जानते हैं वही करना भी चाहते हैं, लेकिन काम मिलता नहीं। मजबूरी में रिक्शा चलाते हैं।

'कारीगर नज़रिया' की ओर से दिलीप कुमार 'दिली' ने इन कारीगरों से कहा कि बिरबली मांग से काम नहीं चलेगा। अब सरकारी कर्मचारी के बराबर पक्की आय की मांग करो और एक कारीगर समाज का एजेण्डा बनाने में शामिल हों।

लोकविद्या जन आन्दोलन की ओर से प्रेमलता सिंह व एहसान अली द्वारा प्रकाशित तथा सत्तनाम प्रेस, पाण्डेयपुर में मुद्रित।